बांग्लादेश का ऐतिहासिक परिपेक्ष्य : एक अध्ययन

* डॉ. कपिल कुमार आनन्द

शोध सारांश

आज पूरी दुनिया जिसे बांग्लादेश के नाम से जानती है, इसकी सभ्यता का बहुत पुराना इतिहास रहा है। इसके इतिहास को अच्छी तरह से जानने और समझने के लिये भारत के विभाजन के पूर्व की स्थिति तथा भारत में ब्रिटिश शासनकाल की स्थिति को समझना अति–आवश्यक है। भारत के विभाजन से पूर्व, पूर्वी बंगाल, बंगाल प्रान्त का ही एक हिस्सा था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल को 1905 में दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया; (i) पूर्वी बंगाल तथा (ii) पश्चिमी बंगाल। हालांकि ब्रिटिश सम्राट ने 12 दिसम्बर, 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द करते हुये 1912 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया। सन् 1947 में भारत विभाजन के समय पूर्वी बंगाल को जिसकी अधिकांश आबादी मुस्लिम थी, पाकिस्तान में सम्मिलित कर दी गयी तथा आगे चलकर इसका नामकरण, पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतर्गत पूर्वी बंगाल शोषण का शिकार रहा, भारत के विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान में सम्मिलित होने के बाद लगातार यह पश्चिमी पाकिस्तानी शासकों की भेद–भावपूर्ण नीति का शिकार रहा। पाकिस्तान में संसद के दिसम्बर, 1970 में आम चुनाव हुये, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजिबुर्रहमान की पार्टी अवामी लीग को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान में जो हालात पैदा हुये, गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया। पूर्वी पाकिस्तान की मुक्तिवाहिनियों ने भारतीय सेनाओं के सहयोग और समर्थन से पश्चिमी पाकिस्तान की सेना को 16 दिसम्बर, 1971 को आत्मसमर्पण करने के लिये मजबूर कर दिया। इसी दिन भारत ने बांग्लोदश को मान्यता दे दी तथा विश्व में एक नए स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

विश्व जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जानता है; इसे बंगाल में 'बोंगो', 'बांग्ला', 'बोंगोदेश' और बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व, यह बंगाल प्रान्त का एक भाग था। बंगाल ब्रिटिश शासन काल के समय सबसे बड़ा प्रान्त था। जिसमें पश्चिमी और पूर्वी बंगाल सहित बिहार व उड़ीसा भी शामिल थे।

बंगाल प्रेसीडेन्सी का विशाल आकार अनेक प्रशासकों के लिए चिन्ता का कारण रहा था। इसलिए सन् 1860 से ही समय–समय पर इसे छोटा करने के सुझाव दिए जाते रहे है। जिसके परिणामस्वरूप सन् 1874 में असम व सिल्हट

को अलग कर दिया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन (1899–1905) द्वारा, बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने, बंगाल को विभाजित करने का कारण प्रशासनिक अव्यवस्था बताया। लेकिन विभाजन का वास्तविक कारण राजनीतिक था। लॉर्ड कर्जन के इस कदम को लेकर राष्ट्रवादी और कैम्ब्रिज इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद हैं। राष्ट्रवादी इतिहासकारो के अनुसार यह कदम जान बूझकर 'फूट डालो और राज करो' की नीति के अन्तर्गत उठाया गया, जबकि कैम्ब्रिज इतिहसकारों ने इसका आधार प्रशासनिक सुविधा बताया।

सन् 1896–97 में असम के चीफ कमिश्नर विलियम वार्ड ने चिटगांव डिविजन, ढाका और मैमनसिंह को अपने प्रान्त में सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया। अंग्रेज अधिकारी असम को प्रशासनिक दृष्टि से अधिक सक्षम एवं व्यावहारिक प्रान्त बनाने पर जोर दे रहे थे। इसी क्रम में 28 मार्च 1903 को बंगाल के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर ने वार्ड के प्रस्ताव को पुनः उठाया। तत्कालीन भारत सचिव रिजले ने, इस स्थानान्तरण योजना का समर्थन दो आधारों पर किया। **प्रथम** बंगाल का बोझ कम होगा, **द्वितीय,** असम का सुधार होगा; ताकि असम के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके। दिसम्बर, 1903 और 19 जुलाई, 1905 की औपचारिक घोषणा के बीच स्थानान्तरण योजना को फ्रेजर, रिजले व कर्जन ने पूर्ण विभाजन में बदल दिया। जिसमें अंततः पूर्वी बंगाल व असम के प्रान्त में, असम के अलावा चिटगांव, ढाका, राजशाही डिवीजन, हिलटिपरा और माल्दा को शामिल कर दिया गया। इस नये प्रान्त की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी; जिसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान तथा 1 करोड़ 20 लाख हिन्दू थे। ढाका को यहॉ की राजधानी बनाया गया। विभाजित बंगाल के, दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा शामिल थे। जिसकी कुल जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी। जिसमें 4 करोड़ 20 लाख हिन्दू तथा 90 लाख मुसलमान थे।

इस कूटनीतिक चाल का प्रमुख उद्देश्य, पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के मुख्यतः हिन्दू राजनीतिज्ञों में दरार डालना था। 19वीं सदी के अन्तिम चरणों में, भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास तीव्रतर होता जा रहा था, जिसका प्रमुख केन्द्र बंगाल था। अंग्रेजों द्वारा इस बढ़ती राजनीतिक चेतना पर आघात करने के उद्देश्य से ही, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। लॉर्ड कर्जन के अनुसार, अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास, कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना एवं बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केन्द्र को समाप्त करना था जहॉ से बंगाल व पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थीं। बंगाल में प्रशासन के भार को कम करने की वैकल्पिक योजनाऍं ये हो सकती थी कि या तो एक 'एक्जीक्यूटिव कांउसिल' की स्थापना की जाती या भाषाई रूप से भिन्न बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाता। लेकिन कर्जन ने राजनीतिक आधारों पर बारम्बार इन सभी विकल्पों को अस्वीकार किया।

इतिहास के पन्नों में बंगाल विभाजन से बांग्लादेश तक

बंगाल विभाजन का उद्देश्य, न सिर्फ बंगालियों को दो प्रशासनिक भागों में बांटकर उनके प्रभाव को कम करना था; बल्कि अंग्रेजी हुकूमत का मूल उद्देश्य, बंगाल में मूल बंगालियों की आबादी को कम कर उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। विभाजन की इस योजना में एक और विभाजन अन्तर्निहित था; धार्मिक आधार पर विभाजन। 19वीं सदी के अन्त में, अंग्रेजों ने कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए मुस्लिम सम्प्रदाय को भड़काने का कार्य शुरू किया। लॉर्ड कर्जन ने सोचा बंगाल विभाजन से ढाका बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले, नए प्रान्त की राजधानी बन जाएगा। ऐसा करने से पूर्वी बंगाल के मुसलमानों में एकता स्थापित होगी; मुसलमानों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी और पूर्वी जिले कलकत्ता की राजशाही से मुक्त हो जायेंगे।

बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर, बंगाल में जंगल की आग की तरह फैली तथा व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये। कर्जन इस प्रतिक्रिया पर तिलमिलाए और गृह सचिव को लिखा कि यदि हमने इस विरोध को अभी

नहीं दबाया तो हम बंगाल को कभी विभाजित नहीं कर पायेंगे। जुलाई, 1905 तक विभाजन की योजना का विरोध मुख्य रूप से पारम्परिक नरमदलीय उपायों का गहन प्रयोग करके किया जाता रहा। कभी अखबारों में लिखकर तो कभी सभाएँ करके और कभी प्रार्थना पत्र देकर। इन उपायों के पूर्णतः असफल हो जाने, पर नए उपायों की खोज की गयी; जिनमें अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार। उल्लेखनीय है कि इसे सर्वप्रथम कृष्णकुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका **'संजीवनी'** के 13 जुलाई, 1905 के अंक में सुझाया गया था।

बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा, 19 जुलाई, 1905 को की गयी। 23 सितम्बर को कलकत्ता में, बंगाल विभाजन की घोषणा के विरूद्ध, 10 हजार हिंदू–मुस्लिम विद्यार्थियों का संयुक्त जुलूस निकाला गया और स्वदेशी आंदोलन में मुसलमान आंदोलनकारियों का एक अत्यन्त सक्रिय व निष्ठावान समूह भी मौजूद था। जिसके प्रमुख नेताओं में गजनवी, रसूल, दीनमोहम्मद, दीदार बख्श, इस्माइल हुसैन शीराजी, अबुल हुसैन, अब्दुल गफूर व लियाकत हुसैन आदि शामिल थे। बंगाल विभाजन के निर्णय को 16 अक्टूबर, 1905 को प्रभावी कर दिया गया। विभाजन के दिन अर्थात् 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में **'शोक दिवस'** के रूप में मनाया गया। इस दिन भाईचारे के प्रतीक स्वरूप, हिन्दू मुसलमानों ने एक–दूसरे को राखी बांधी तथा शोक प्रतीक के रूप में, चूल्हा नहीं जलाया गया। हिन्दू इस विभाजन से असहमत थे; उनका तर्क था कि बंगाल सदैव इतिहास और भाषा से संयुक्त रहा है।

दिसम्बर, 1911 में ब्रिटिश सम्राट जार्ज पंचम् व महारानी मैरी के भारत आगमन पर उन के स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसम्बर, 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करते हुए 1912 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया और बिहार व उड़ीसा दो भिन्न–भिन्न प्रान्त बना दिये। भारतीय राजनीति में एक बड़ा फेरबदल करते हुए सम्राट जार्ज पंचम ने कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की तत्कालीन वायसराय हार्डिंग को अनुमति दे दी। 1 अप्रैल, 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल 1943 में एक भीषण अकाल से ग्रस्त हुआ। जिसमें अनुमानतः 30 लाख लोगों की मौत हुई।

अंग्रेजों ने भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया। देश के टुकड़े करके भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बना दिये गये। पूर्वी बंगाल जहॉ की अधिकांश जनता मुस्लिम थी व आर्थिक दृष्टि से कमजोर थी। उन्होंने भारत विभाजन के समय पाकिस्तान के साथ मिलना स्वीकार किया। भारत की स्वतन्त्रता के बाद, पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बना। पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान में शामिल होने के कारण 1958 में इसका नामकरण पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से, भौतिक रूप से व सजातिविषयक रूप से, बांग्लादेश के निर्माण तक भिन्न रहा।

पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बांग्लादेश) की पश्चिमी पाकिस्तान से दूरी लगभग 1300 मील है। स्वतन्त्रता के पश्चात् पाकिस्तान की राजधानी और केन्द्रीय सरकार का मुख्यालय, पश्चिमी पाकिस्तान के करांची शहर में स्थापित किया गया। जबकि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी (करीब 56 प्रतिशत) पूर्वी पाकिस्तान में निवास करती थी। परन्तु भौगोलिक दृष्टि से यह पश्चिमी पाकिस्तान से छोटा था। यह हिस्सा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा शोषित रहा। शीध्र ही यहॉ के बंगाली लोगों का पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं की नीतियों से मोह भंग हो गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद ज़िन्ना ने, मार्च, 1948 में घोषणा की, कि पाकिस्तान की राज्य भाषा उर्दू होनी चाहिये। पूर्वी पाकिस्तान के लोग, ज़िन्ना की घोषणा से भयभीत हो गये क्योंकि वे लोग न केवल बंगाली भाषा बोलने वाले थे और अपनी भाषा की परम्परा और विपुलता पर भी गर्व करते थे। परन्तु फिर भी उर्दू को एक मात्र, राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया। बंगालियों ने महसूस किया कि अब उर्दू बोलने वाले लोगों के लिये, समाज

और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के साथ–साथ पाकिस्तान में, नौकरी प्राप्त करने के अवसरों में भी, यह बहुत फायदे मंद होगी। जबकि बंगाली बोलने वालों को इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता।

दोनों प्रान्तों के मध्य विभेद को सम्भालना मुश्किल हो गया। मुख्तयः तब जब पूर्वी पाकिस्तान के राजनीतिक दल अवामी लीग ने दिसम्बर, 1970 के, संसद के चुनावों में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। पाकिस्तान में मार्च, 1971 से 16 दिसम्बर, 1971 तक गृह युद्ध जारी रहा। पूर्वी पाकिस्तान ने, भारतीय सेनाओं की सहायता से पश्चिमी पाकिस्तान को युद्ध में पराजित कर दिया। इस प्रकार अब तक जो, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था; वह 16 दिसम्बर, 1971 को एक स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में उठ खड़ा हुआ। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य है तथापि, सांस्कृतिक और सामाजिक रूपों से, बंगाल के ये दोनों अंश, आज भी बंगाली भाषा के अलावा कई अन्य बातों में एक दूसरे के अप्रत्यक्ष साझेदार बने हुए है।

निष्कर्ष

भारत की आजादी से पहले पूर्वी बंगाल (वर्तमान में बांग्लादेश) बंगाल प्रान्त का एक भाग था, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी बंगाल सहित बिहार व उड़ीसा प्रान्त भी शामिल थे। 19 वीं सदी के अंतिम चरणों में भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी, जिसका प्रमुख केन्द्र बंगाल ही था। अंग्रेजों द्वारा इस बढ़ती राजनीतिक दखल पर आघात करने के उद्देश्य से ही बंगाल का विभाजन किया गया था। किन्तु इस बंग–भंग का जबरदस्त विरोध हुआ और परिणामतः दिल्ली दरबार में 12 दिसम्बर, 1911 को ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करते हुए 1912 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया, लेकिन जिन्ना ओर मुस्लिम लीग की नीतियों के कारण यह जुडाव वैसा नहीं हो पाया जैसा कि बंगाल विभाजन से पूर्व था।

ब्रिटिश शासन की गुलामी से आजादी पाने के लिये कई आन्दोलन हुए जिसके परिणामस्वरूप देश स्वतंत्र हो सका। लेकिन मुस्लिम लीग के '**द्वि–राष्ट्र सिद्धान्त**' के कारण देश दो भागों में विभाजित हो गया, जिसमें भारत व पाकिस्तान दो अलग–अलग राष्ट्रों के रूप में सामने आये। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में शामिल हुआ, जिसके कारण 1958 में इसका नामकरण पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया। **भौगोलिक दृष्टि** से यह पश्चिमी पाकिस्तान से छोटा तथा **आर्थिक दृष्टि** से पिछड़ा हुआ था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में कम क्षेत्रफल में अधिक आबादी तथा उद्योगों का न लगना इसकी गरीबी के मुख्य कारण थे। पाकिस्तान के शासक जो अधिकांश पाकिस्तान के पश्चिमीं हिस्से का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की ओर से अपने समर्थन पर आंखे मूंद ली थी। पाकिस्तान द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं बनायी गई उनमें भी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा न के बराबर था।

पूर्वी पाकिस्तान से कच्चा माल विदेशों व पश्चिमी पाकिस्तान के कारखानों के लिये लाया जाता था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के उपनिवेश का ही शिकार रहा। पूर्वी पाकिस्तान से निर्यातित कच्चे माल से जो विदेशी मूद्रा प्राप्त होती थी, उस पर भी पश्चिमी पाकिस्तान का एकाधिकार था। पाकिस्तान के विकास के बजट का 70 फीसदी पश्चिमी पाकिस्तान पर खर्च होता था तथा पूर्वी पाकिस्तान पर बजट का केवल 30 प्रतिशत ही खर्च होता था, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की कुल आबादी की आधे से अधिक जनसंख्या रहती थी। इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरियों में भी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की संख्या न के बराबर थी, क्योंकि सरकार तथा प्रशासन में पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का हावी होना महत्वपूर्ण रहा था। भाषा और सांस्कृतिक दृष्टि से भी पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से भिन्न होने के कारण सदैव शोषित ही रहा।

उपरोक्त कारणों से ज्ञात है कि पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोगों का पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं की नीतियों से मोह भंग होने लगा, और इसी के चलते दिसम्बर, 1970 के संसदीय चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान के राजनीतिक दल

'**अवामी लीग**' को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। जिसकी वजह से पाकिस्तान में मार्च, 1971 से 16 दिसम्बर, 1971 तक गृह युद्ध रहा। पूर्वी पाकिस्तान ने भारतीय सेनाओं की सहायता से पाकिस्तान को युद्ध में हराया। 16 दिसम्बर, 1971 की शाम को बांग्लादेश के रेसकोर्स मैदान में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने अपने लगभग 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसर्मपण कर दिया। इस प्रकार विश्व पटल पर एक स्वतंत्र और सम्प्रभु राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ।

***सहायक प्रोफेसर**
राजनीति विज्ञान
एस.एस.जैन सुबोध पी.जी. (स्वायत्तशासी)
महाविद्यालय, जयपुर (राज.)

संदर्भ–सूची

1. अहमद, सलाहुद्दीन (2004) ***बांग्लादेश पास्ट एण्ड प्रजेन्ट***. नई दिल्ली :ए.पी.एच. पब्लिशिंग कार्पोरेशन
2. आनन्द, कपिल कुमार (2006) ***भारत–बांग्लादेश सम्बन्धः नवें दशक में भारत की विदेश नीति का एक अध्ययन*** (अनपब्लिशड डॉक्टरल थीसिस), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
3. खन्ना, एस.के. व सुदर्शन, के.एन. (1998) ***एनसाइक्लोपीड़िया ऑफ साउथ एशिया, बांग्लादेश***. नई दिल्ली :ए.पी.एच. पब्लिशिंग कार्पोरेशन
4. रशीद, हरूणउर (2002) ***इन्डो–बांग्लादेश रिलेशन्सः ऐन इनसाइडस् व्यू*** नई दिल्ली :हर–आनन्द पब्लिकेशन्स
5. Please See this Website

   https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Bangladesh